## केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से उत्तर प्रदेश को भारी-भरकम धनराशि मिलने की उम्मीद

# यूपी को विकास के लिए करों से मिलेंगे 3.47 लाख करोड़ रुपये

■ हेमंत श्रीवास्तव

लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेश 2024-25 के अंतरिम बजट में यूपी के विकास को और गति मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, करों व शुल्कों में हिस्सेदारी से राज्य को करीब 3.47 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। अकेले केंद्रीय करों व शुल्कों में बन रही यूपी की हिस्सेदारी के तहत 218816.84 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 20681 करोड़ रुपये अधिक है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में राज्यों के लिए केंद्र सहायतित योजनाओं में व्यवस्था की है। इसमें यूपी को 90 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह केंद्रीय योजनाओं में करीब 7000 करोड़ रुपये, विकसित भारत योजना के तहत यूपी को 14000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 14000 करोड़ रुपये की धनराशि 50 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी यूपी को जाएगी। इसी तरह राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत यूपी को 17939 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह रकम भी 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। इस लिहाज से केंद्रीय करों और विभिन्न योजनाओं से यूपी को विकास के मद में 2024-25 में कुल करीब 3.47 लाख करोड़ रुपये मिल जाएंगे।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी 198135.05 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत इस बजट से प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रदेश सरकार की कोशिशों को बल मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, छतों पर सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, लखपति दीदी, दो करोड़ नए आवास, नए मेडिकल कालेजों का निर्माण आदि की व्यवस्थाओं का अधिकाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।

**अकेले आयकर में ही यूपी की हिस्सेदारी 75716 करोड़ रुपये:** अंतरिम बजट में केंद्र सरकार के करों व शुल्कों में सबसे अधिक 17.939 फीसदी हिस्सेदारी यूपी की है। यूपी को दो लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये केंद्र सरकार 2024-25 में देगी। इनमें सबसे अधिक धनराशि आयकर से 75716.75 करोड़, कारपोरेशन टैक्स से 68715..81 करोड़ और सेंट्रल जीएसटी से 66898.49 करोड़ रुपये मिलेंगे। इनके अलावा कस्टम 4465.09 करोड़, एक्साइज ड्यूटी से 2669.85 करोड़ तथा सर्विस टैक्स से 7.35 करोड़ तथा अन्य करों से 345.68 करोड़ रुपये का अनुमान है।

### बजट की योजनाओं का प्रदेश को मिलेगा लाभ

**50 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण के लिए 75 हजार करोड़ की योजना**

**एक करोड़ परिवार को हर महीने सौर ऊर्जा से 300 यूनिट मुफ्त बिजली**

- 2.18 लाख करोड़ केंद्रीय करों से और 90 हजार करोड़ केंद्र सहायतित योजनाओं से मिलेंगे
- 7 हजार करोड़ केंद्रीय योजनाओं में, 14 हजार करोड़ विकसित भारत योजना से
- 17939 करोड़ राज्यों को विशेष सहायता मद से कुल 3.47 लाख करोड़ की धनराशि मिलेगी
- निवेश बढ़ाने को पूरा करने के लिए केंद्रीय योगदान
- एमएसएमई के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों व प्रौद्योगिकियों
- आकांक्षी जिलों व ब्लाकों के तेजी से विकास में सहायता
- ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले दो करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना
- किराये के मकानों व झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए स्वयं की मकान योजना
- आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य देखरेख में आशा, आंगनबाड़ी को शामिल किए जाने
- आधुनिक भंडारण व प्रसंस्करण में निजी व सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने
- आत्मनिर्भर तिलहन अभियान योजना के तहत खरीद, बाजार व मूल्यवर्धन